केन्द्रीय बजट 2012–13 एवं रोज़गार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12

केन्द्रीय बजट 2012 –13

I उद्देश्य

उद्देश्यों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है.

(प) घरेलू माँग प्रेरित विकास में तेजी लाना

(पप) निजी निवेश में उच्च विकास के तीव्र पुनः प्रचलन की स्थितियाँ सृजित करना.

(पपप) आपूर्ति से जुड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना.

(पअ) कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक उपाय करना.

(अ) उन्नत वितरण प्रणालियों, नियंत्राण एवं पारदर्शिता के समन्वित कार्यान्वयन में तीव्रता लाना और जनजीवन में काले धन तथा भ्रष्टाचार की समस्या को रोकना.

II कौशल विकास

– राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को 1000 करोड़ रु. आबंटित किए जा रहे हैं. 10 वर्षों के अंत में, इसके अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से 62 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने तथा निजी क्षेत्रा में व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता प्रति वर्ष 12.5 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है.

– बाजार उन्मुखी कौशल प्राप्त करने में युवा वर्ग के लाभ के लिए कौशल विकास हेतु संस्थागत क्रेडिट के प्रवाह में सुधार लाने के लिए एक पृथक क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित की जाएगी.

– जम्मू–कश्मीर में ''हिम्मत'' नामक एक नई योजना चलाई गई है. इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1,00,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देना है. इस कार्यक्रम की सम्पूर्ण लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी.

III ग्रामीण रोज़गार एवं महिल अधिकारिता

– ग्रामीण क्षेत्राों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए एम.जी.–एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत आबंटन के लिए 33,000 करोड़ रु. की राशि रखी गई है, जो 17.5% कटौती का द्योतक है. यह कटौती पिछले वित्त वर्ष में कम व्यय एवं कृषि मंत्राालय द्वारा खेती के मौसम में मजदूरों की कमी होने के कारण ऋण–स्थगन की मांग के आधार पर की गई है.

– स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) नाम दिया गया है. एन.आर.एल.एम. के लिए 3915 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है.

– महिला स्व–स्वास्थ्य समूह विकास निधि के 300 करोड़ रु. की समग्र निधि बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है.

– सिविल सोसायटियों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्राों में लगभग 117 जिलों को शामिल करते हुए, की पहल को समर्थन तथा महत्व देने के लिए भारतीय भारत आजीविका फाउंडेशन की स्थापना करना.

– केन्द्र ने महिला स्व–सहायता समूहों को 7% की इमदादी दर पर 3.00 लाख रु. तक का ऋण देने और ऋण समय पर लौटाने वालों को 3% अतिरिक्त इमदाद देने का निर्णय लिया है. इसके पहले चरण में 150 जिलों के 600 खंडों को शामिल किया जाएगा.

– 11 से 18 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के स्व–विकास के लिए पोषण आवश्यकताओं तथा शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना के लिए 750 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है.

IV सरकार ने एक नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत सभी मंत्राालय एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रम अपने कुल वार्षिक क्रय में से न्यूनतम 20% क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) से करेंगे, ताकि इस क्षेत्रा, जो कि देश में एक बड़ा नियोक्ता है, की बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जा सके.

आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12

(i) भारत – तेजी से बढ़ती हुई अर्थ–व्यवस्था

एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.9% की निम्न विकास दर होने के बावजूद भारत विश्व की सबसे तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था है, जबकि विश्व की तीव्र गति से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं सहित अन्य सभी बड़े देश गंभीर मंदी का सामना कर रहे हैं.

(ii) आर्थिक मंदी

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का मुख्य कारण विश्व मंदी है. इसके अतिरिक्त घरेलू तथ्यों जैसे आर्थिक नीति कड़ी करना, अत्यधिक मुद्रा स्फीति एवं निवेश एवं औद्योगिक कार्यों में मंदी इसके अन्य कारण हैं.

(iii) मुद्रास्फीति

मुद्रा –स्फीति दर 6.5–7% है, जिसके वर्ष के अंत तक कम होने की संभावना है, थोक खाद्य स्फीति दर फरवरी 2010 के 20.2 प्रतिशत से घटकर जनवरी, 2012 में 1.6 प्रतिशत हो गई है.

(iv) रोज़गार

भारत, 2009 से विश्व मंदी तथा सामान्य रोज़गार के विपरीत प्रभावों का सामना करने में सक्षम रहा है. देश में, सितंबर, 2011 को समाप्त एक वर्ष की अवधि में नौ लाख से भी अधिक नए रोज़गार सृजित हुए. इन नए सृजित रोज़गारों में से लगभग 8 लाख रोज़गारों की घोषणा सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थक सेवाओं (आई.टी.ई.एस.) क्षेत्राों ने की.

(v) एम.जी. – एन.आर.ई.जी.ए.

महात्मा गांधी – राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम से परिवारों को जोड़ने की संख्या 2010–11 के दौरान बढ़ कर 5.49 करोड़ हो गई. इस योजना की पारदर्शिता एवं दायित्व/साख को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने, सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यों से जुड़ी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) एवं बायोमीट्रिक्स सेवा प्रदाता योजना प्रारंभ की है.

(सम्पादकीय टीम, रोज़गार समाचार द्वारा संकलित)